



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1965 (फाल्गुन 29, 1886)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1965 (PHALGUNA 29, 1886)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 5 मार्च, 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 5th March, 1965 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
20	27 फरवरी 1965 27th Feb., 1965	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance.	वित्त मंत्री का बजट भाषण, 1965-66 Finance Minister's Budget speech, 1965-66
21	No. 15 ITC(PN)/65 dated 5th Feb., 1965	Ministry of Commerce.	Indo Afghan Trade Arrangement for 1964.65 and 1965-66 basis on counterbalancing of Imports by exports.
22	स (20)8-टोरि/64 दिनांक 30 दिसम्बर 1964	वाणिज्य मंत्रालय	टोरिफ आयोग के लिए चीनी की लागत ढांचे के लिये जांच करना आवश्यक नहीं है

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची CONTENTS

पृष्ठ Pages	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 139	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं —
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं 223	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं 141
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम —
	भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रश्न समितियों की रिपोर्टें —

पृष्ठ	पृष्ठ
Pages	Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .. 461	भाग III—खंड 2—एवंस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस .. 91
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं 965	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश 75	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .. 2351
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 167	भाग IV—नगर-सरकारी व्यक्तियों और नगर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .. 57
	पूरक सं० 12—
	13 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .. 369
	20 फरवरी, 1965 को समाप्त होनेवाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उसने अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े .. 379
<hr/>	
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 139	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) 965
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 223	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 75
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence —	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 167
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence 141	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 91
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations —	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills —	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2351
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 461	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 57
	SUPPLEMENT No. 12 -
	Weekly Epidemiological Reports for week-ending 13th March 1965 369
	Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 20th February 1965 379

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

योजना आयोग

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1965

श्रम नीति सम्बन्धी पैनल

संख्या श्रम और रोजगार (श्रम) 11-1-64—इसी संख्या के दिनांक 30-1-65 के संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, प्रा० बी० के० आर० बी० राव, सदस्य योजना आयोग के स्थान पर श्री तरलांक सिंह, सदस्य योजना आयोग पैनल के अध्यक्ष होंगे।

एम० बट्ट, संयुक्त सचिव

बिज्ञ मंत्रालय

(राजस्व तथा सम्पत्ति विधि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1965

[एफ० संख्या 7(21) एन० एस०/64] केन्द्रीय सरकार, एन० द्वारा, 4½ प्रतिशत व्याज वाले दशवर्षीय रक्षा जमा-पत्रों में सम्बन्धित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की, 1 नवम्बर 1962 की अधिसूचना संख्या एफ० 3(21)—2/एन० एस०/62 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना के—

(क) पैराग्राफ 5 के—

(i) उप-पैराग्राफ (क) में, “जो मूल रकम की वापसी के लिए परिपक्व हो गये हैं” इन शब्दों के बाद, “अथवा 5-वर्षीय व्याज-मुक्त इनामी बांड, 1965” शब्द और अंक जोड़े जायेंगे ;

(ii) उप-पैराग्राफ (ख) में, अन्त में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा :—

“5-वर्षीय व्याज-मुक्त इनामी बांड, 1965, वापस करके जमा की गयी रकमों पर इस रीति से व्याज लगेगा :

(i) यदि रकम 31 दिसम्बर, 1965 से पहले जमा की गयी हो, तो व्याज 1 अप्रैल, 1965 से लगेगा, चाहे बांड तत्सम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ, बांड प्राप्त करने के लिए अधिकृत किये गये किसी कार्यालय में किसी भी तारीख को पेश किये जायें ;

(ii) यदि रकम 31 दिसम्बर, 1965 के बाद जमा की गयी हो, तो व्याज उस तारीख से लगेगा जिस तारीख को बांड, आवेदन-पत्र के साथ ऐसे किसी कार्यालय में पेश किये गये हो।”

(iii) उप-पैराग्राफ (ग) के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ जोड़ा जायेगा :—

(घ) “अभिदान के रूप में पेश किये गये 5-वर्षीय व्याज-मुक्त इनामी बांड, 1965, उनके पृष्ठ-भाग पर यह लिखकर निपटा दिये जाने चाहियें : “रकम मिल गयी”।

हरयाक्षर

(ख) आवेदन-पत्र के फार्म में, पैराग्राफ 1 में, “निपटायें गये 3½ प्रतिशत व्याजवाले 10-वर्षीय राजकोप बचत जमा-पत्र संख्या (संख्याएं)” इन शब्दों, अंकों और ब्रैकेटों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—“5-वर्षीय, व्याजमुक्त इनामी बांड, 1965 संख्या (संख्याएं)”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1965 में लागू होगी।

बी० एस० राजगोपालन अनु-सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1965

निर्यात सम्बन्धित परिपदों के कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति :

सं० 4(14)/64-ई० पी० (कोआर्ड)—वाणिज्य मन्त्रालय के संकल्प सं० 4(14)/64-ई० पी० (कोआर्ड) दिनांक 9 सितम्बर, 1964 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, भारत सरकार प्रसन्नता-पूर्वक समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन देने की तिथि को बढ़ा कर 30 अप्रैल, 1965 करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

एस० हामिद, संयुक्त सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1965

सं० 6-32/64-सी० जी०—भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित दिनांक 17 अगस्त, 1964 के प्रस्ताव संख्या 6-32/64-सी० (जी०) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को भी कृषि वैज्ञानिकों के पैनल में सम्मिलित कर लिया जाये :—

1. डा० एस० एम० सिक्का,
कृषि आयुक्त,
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्,
खाद्य और कृषि मन्त्रालय,
(कृषि विभाग),
नई दिल्ली।

2. डा० जे० एम० कवर,
अनुसन्धान निदेशक,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना।
और

3. डा० एम० प्रधान,
प्रमुख वनस्पति विज्ञान प्रभाग,
भारतीय कृषि अनुसन्धान संग्रहालय,
नई दिल्ली।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों और विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय प्रधान-मन्त्री सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां), कृषि वैज्ञानिकों के पैनल के समस्त सदस्यों, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्रों के कृषि और पशु-पालन निदेशकों, खाद्य और कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के अन्तर्गत समस्त सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ग० रा० कामत, सचिव

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 मार्च 1965

सं० 38/7/64-एडवर्टाइजिंग—इस मन्त्रालय की अधि-सूचना संख्या 41/23/58-ए० बी० तारीख 21 मार्च, 1960 द्वारा प्रख्यापित और अधिसूचना संख्या 23/19/62-एडवर्टाइजिंग, तारीख 14 फरवरी, 1964 द्वारा संशोधित, छपाई और डिजाइन के लिये राज-पुरस्कार नियमावली के नियम 4 और 19 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि नियम 4 में क्रम संख्या 8 और 18 की वर्तमान प्रविष्टियों तथा नियम 6 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

पुरस्कारों की श्रेणियाँ

4. पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिये जायेंगे :—

8. वार्षिक पत्रिकाएं

18. प्रचार पुस्तिकाएं और कला पत्रिकाएं।

पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये पात्रता

6. नियम 8 और 9 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 4 में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत प्रस्तुत कोई भी ऐसी सामग्री पुरस्कार प्रतियोगिता के लिये मान्य होगी जो 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के पुरस्कार-वर्ष के दौरान भारत संघ ही में पूर्णतः तैयार की गई हो।

टिप्पणी : (1) कैलेंडर वर्ष सम्बन्धी उपर्युक्त परिवर्तन छपाई और डिजाइन के लिये 11वें राज-पुरस्कार से लागू होगा। छपाई और डिजाइन के लिये 10वें राज-पुरस्कार के लिये वह सामग्री प्रविष्ट हो सकेगी जो 15 अगस्त, 1963 से लेकर 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में तैयार की गई हों।

(2) यह आवश्यक है कि प्रविष्ट वस्तुओं की डिजाइनकारी और छपाई भारत में ही हुई हो, वरना वे पुरस्कार के लिये स्वीकृत नहीं होंगी।

पुरस्कार प्रतियोगिता की सूचना और पुरस्कार के लिए सामग्री भेजने की विधि

8. पुरस्कारार्थ सामग्री भेजने की सूचना प्रैस नोट या सार्वजनिक सूचना के किसी ऐसे अन्य माध्यम के जरिए, जिसे सरकार उचित समझे, मुद्रकों, प्रकाशकों, विज्ञापकों, विज्ञापन, एजेंसियों, वाणिज्य कला गृहों, आदि को दी जाएगी। प्रैस नोट या अन्य सूचना में, सामग्री भेजने के लिए सूचना प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम 30 दिन की अवधि दी जाएगी।

एस० पद्मभाभन्, अवर सचिव

निर्माण तथा आवास मन्त्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1965

सं० 14(30)/64-ई० डब्ल्यू० 1—भारत सरकार ने उस अवधि को 30 अप्रैल 1965 तक बढ़ा दिया है, जिसमें कि संकल्प सं० 14(30)/64-ई० डब्ल्यू० 1 तारीख 17 अगस्त, 1964 के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया और कार्य-प्रणाली के परीक्षण के लिए बनाई गई अध्ययन टोली (स्टडी टीम) को अपनी रिपोर्ट दे देने की संभावना थी।

आवेश

2. आदेश दिया गया कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाये और सामान्य सूचना के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जाये।

रामचन्द्र मेहरा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मन्त्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1965

संख्या WB-3(3)/65—रबड़ बागान उद्योग के केन्द्रीय मजदूर बोर्ड ने, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या WB-3(5)/61/2, तारीख 7 जुलाई, 1961 द्वारा की थी, क्षेत्रीय और कारखाना कामगरो के मजदूरी विन्यास के बारे में सिफारिशें कर दी हैं, जो कि परिशिष्ट में दी गई हैं।

2. सरकार ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने और नियोजकों से उन्हें यथाशीघ्र लागू करने के लिए अनुरोध करने का निश्चय कर लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० एल० मेहता, अतिरिक्त सचिव

परिशिष्ट

रबड़ बागान उद्योग का केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड

रबड़ बागान उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड क्षेत्रीय और कारखाना कामगारों की मजदूरी दरों के बारे में, जो कि रबड़ बागान उद्योग में 1 मई, 1964 से 5 साल तक प्रचलित रहनी चाहिये, सर्वसम्मति निष्कर्षों पर पहुंचा है। बोर्ड ने कुछ अन्य प्रासंगिक मामलों के बारे में भी निर्णय किए हैं; परन्तु बोर्ड अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि रबड़ बागानों में नियुक्त क्लर्कों, चिकित्सा तथा शैक्षिक कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों आदि की मजदूरी अभी तय करनी बाकी है। अतः बोर्ड द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने में कुछ और समय लगेगा। इस बीच निर्वाह-सर्व में वृद्धि हो गई है। चाय बागान उद्योग के केन्द्रीय बोर्ड ने दक्षिण के कामगारों के लिए 1 मई, 1964 से दूसरी अंतरिम मजदूरी वृद्धि मंजूर की है। इस बोर्ड ने दूसरी अंतरिम मजदूरी वृद्धि मंजूर नहीं की है क्योंकि यह पांच साल तक लागू रहने वाले मजदूरी-विन्यास को अंतिम रूप दे रहा था। काफी बागानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में भी काफी बागान उद्योग के मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वृद्धि हो गई है। इस बोर्ड ने भी कामगारों को 1-5-1964 से मजदूरी बढ़ाने का निर्णय किया है। अतः इसका विचार है कि रबड़ बागानों में क्षेत्रीय और कारखाना कामगारों को इसकी सिफारिशों का लाभ तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तदनुसार बोर्ड रबड़ बागान उद्योग के

कामगरो के लिए 1 मई, 1964 से निम्नलिखित दैनिक मजदूरी-दरों की सफारिश करता है :—

(क) केरल और मद्रास :

(1) अमानी पर काम करने वाले क्षेत्रीय कामगरो की मजदूरी निम्नलिखित होनी चाहिए :—

पुरुष	2.10 रु०
महिलाएं	1.80 रु०
किशोर	1.31 रु०
बालक	1.05 रु०

(2) कारखाना कामगरो की मजदूरी निम्नलिखित होनी चाहिए :—

पुरुष	2 30 रु०
महिलाएं	1.95 रु०
किशोर	1 44 रु०

(3) टैप्स के लिए उजरती दरें और गुजारेलायक मजदूरी :—

(क) उजरती दरों के लिए, रबड एस्टेटों को पिछले वर्ष की प्रति एकड़ उपज के आधार पर निम्नलिखित मात्र श्रेणियों में रखा जाना चाहिए :—

श्रेणी	उपज
I	110 कि० ग्रा० तक
II	110 किलोग्राम से अधिक और 180 कि० ग्रा० तक
III	180 कि० ग्रा० से अधिक और 270 कि० ग्रा० तक
IV	270 कि० ग्रा० से अधिक और 360 कि० ग्रा० तक
V	360 कि० ग्रा० से अधिक और 450 कि० ग्रा० तक
VI	450 कि० ग्रा० से अधिक और 540 कि० ग्रा० तक
VII	540 कि० ग्रा० से अधिक

(ख) (क) में उल्लिखित श्रेणियों का मानक उत्पादन इस प्रकार होना चाहिए :—

श्रेणी	प्रति टैपिंग ब्लॉक मानक दैनिक उत्पादन
I	1-1/2 किलोग्राम
II	3 किलोग्राम
III	5 किलोग्राम
IV	7 किलोग्राम
V	10 किलोग्राम
VI	12-1/2 किलोग्राम
VII	15 किलोग्राम

(ग) टैपिंग ब्लॉक के लिए साधारण टैपिंग पद्धति निम्नलिखित होगी :—

(i) 250 वृक्ष जहां प्रति एकड़ 100 या कम वृक्ष खड़े हैं।

(ii) अन्य मामलों में 300 वृक्ष जैसा कि इस समय है।

(घ) टैप्स को 1 04 रु० की गुजारे लायक मजदूरी दी जानी चाहिए और इसके अलावा उन्हें उनके उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित दरों पर मजदूरी दी जानी चाहिए :—

श्रेणी	मानक उत्पादन तक प्रति 1/2 कि० ग्रा० पैसे में	मानक उत्पादन से ऊपर उत्पादन के लिए प्रति 1/2 कि० ग्रा० पैसों में दर
I	39	7
II	20	7
III	13	8
IV	9-1/2	8
V	8 3	10
VI	6 64	10
VII	5 5	10

(ख) मैसूर

(1) अमानी पर काम करने वाले क्षेत्रीय कामगरो की मजदूरी इस प्रकार श्रेणी होनी चाहिए :—

पुरुष	—	1.80 रु०
महिलाएं	—	1 40 रु०
किशोर	—	1 10 रु०
बालक	—	0.90 रु०

(2) कारखाना कामगरो की मजदूरी इस प्रकार होनी चाहिए :

पुरुष	—	1 90 रु०
महिलाएं	—	1 50 रु०
किशोर	—	1 15 रु०

(3) टैप्स के लिए उजरती दरें और गुजारे-लायक मजदूरी :—

उजरती दर के लिए रबड एस्टेटों की श्रेणियां, उनका मानक उत्पादन और उजरती दर पर काम करने वाले टैप्स की उनके उत्पादन के आधार पर मजदूरी की दरें वही होनी चाहिए, जो कि मद्रास और केरल राज्यों के बारे में निर्दिष्ट की गई हैं। परन्तु मैसूर राज्य में गुजारेलायक मजदूरी 0 74 रु० प्रति-दिन होनी चाहिए।

बाद के वर्षों के लिए मजदूरों की मजदूरी के सम्बन्ध में बाई की सफारिशें बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।

एन० अहमद
महोदय

ह०/- अध्यक्ष और सदस्य

कायम्बतूर तारीख 29 जनवरी 1965

PLANNING COMMISSION**RESOLUTION***New Delhi, the 8th March 1965***PANEL ON LABOUR POLICY**

No. L&E(L)11-1/64.—In partial modification of Resolution No. L&E(L)11-1/64, dated 30-1-1965, Shri Tarlok Singh, Member, Planning Commission will be the Chairman of the Panel on Labour Policy in place of Prof. V. K. R. V. Rao, Member, Planning Commission.

M. BUTT, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)***New Delhi, the 10th March 1965*

No. F. 7(21)-NS/64.—The Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. F. 3(21)-2/NS/62, dated the 1st November 1962, relating to 4½ per cent Ten-Year Defence Deposit Certificates, namely:

In the said notification—

(a) in paragraph 5—

(i) in sub-paragraph (a), after the words “which have matured for refund of principal”, the words and figures “or 5-Year Interest-Free Prize Bonds, 1965” shall be inserted;

(ii) in sub-paragraph (b), the following sentence shall be inserted at the end, namely:—

“Interest on deposits made by tendering 5-Year Interest-Free Prize Bonds, 1965 will,—

(i) if made before the 31st December, 1965, run from the 1st April 1965, irrespective of the date on which the Bonds together with the relevant application are presented at an office authorised to receive deposits;

(ii) if made after the 31st December 1965, run from the date on which the Bonds together with the application are presented at such an office”

(iii) after sub-paragraph (c), the following sub-paragraph shall be inserted namely:—

“(d) The 5-Year Interest-Free Prize Bonds, 1965 tendered by way of subscription should be discharged on the reverse in the manner indicated below:

‘Received payment.

Signature”

(b) in the Form of Application, in paragraph 1, after the words, figures and brackets “Discharged 3½ per cent 10-Year Treasury Savings Deposit Certificates No. (s)”, the following shall be inserted, namely:—

“5-Year Interest-Free Prize Bonds, 1965.

No. (s)”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April 1965.

V. S. RAJAGOPALAN, Under Secy.

New Delhi, the 11th March 1965

No. F. 25(43)-NS/63.—The Five-Year Interest-Free Prize Bonds, 1965 which were issued in terms of the Government of India, Ministry of Finance Notification No. F. 4(1)-W&M/60, dated the 1st March 1960, will be due for repayment on the 1st April 1965. The following offices are authorised to receive and arrange for the repayment of the Prize Bonds namely:—

(i) Offices of the Reserve Bank of India at Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore and Nagpur;

(ii) Branches of the State Bank of India and its subsidiary banks conducting Government treasury work;

(iii) Head Post Offices;

(iv) Departmental Sub-Post Offices; and

(v) Non-banking treasuries and sub-treasuries.

2. (i) The Offices of the Reserve Bank of India and branches of the State Bank of India and its subsidiary Banks conducting Government treasury work, will accept and repay all Prize Bonds irrespective of the office of issue.

(ii) The Post Offices will accept and repay the Prize Bonds issued by Post Offices only.

(iii) A non-banking Treasury or Sub-Treasury will accept and repay only the Prize Bonds issued by it.

A. G. KRISHNAN, Officer on Special Duty.

MINISTRY OF COMMERCE**RESOLUTION***New Delhi, the 5th March 1965***COMMITTEE TO REVIEW THE WORKING OF EXPORT PROMOTION COUNCILS**

No. 4(14)/64-EP(Coord).—In partial modification of the Ministry of Commerce Resolution No. 4(14)/64-EP(Coord), dated the 9th September 1964, the Government of India has been pleased to extend the period of submission of Report by the Committee up to 30th April 1965.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. HAMID, Jt. Secy.

RESOLUTION*New Delhi, the 11th March 1965*

No. 9(3)/Tex(B)/65.—The Government of India have decided to appoint Sarvashree Bharat Ram, C/o Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd., Bara Hindu Rao, Delhi, Padampat Singhania, Kamla Tower, Kanpur and T. P. Chakravarti, C/o. Shri Annapurna Cotton Mills Ltd., P. 10, New Howrah Bridge, Approach Road, Calcutta, as non-official members of the Cotton Textiles Consultative Board reconstituted under the Ministry of International Trade Resolution No. 1(2)/Tex(A)/60, published in the Gazette of India Extraordinary on the 8th January 1964, vice Sarvashree Lalchand B. Sethi, Purushottamdas D. Singhania and Ramanlal Chimanlal.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED that the Resolution be communicated to all concerned.

T. S. KUNCHITHAPATHAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE**(Department of Agriculture)****RESOLUTION***New Delhi the 5th March 1965*

No. 6-32/64-C(G).—The Government of India have decided that—

1. Dr. S. M. Sikka, Agricultural Commissioner, Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture), New Delhi;

2. Dr. J. S. Kanwar, Director of Research, Punjab Agricultural University, Ludhiana; and

3. Dr. S. Pradhan, Head of the Division of Entomology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi,

will also be members of the Panel of Agricultural Scientists constituted under this Ministry's Resolution No. 6-32/64-C(G), dated the 17th August, 1964.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies), All Members of the Panel of Agricultural Scientists, Directors of Agriculture and Animal Husbandry in all the States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

G. R. KAMAT, Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER**RESOLUTION***New Delhi, the 6th March 1965*

No. DW.I.501(4)/64.—Further to this Ministry Resolution No. DW.V.501(4)/64, dated the 9th October 1964, Government are pleased to extend the period for submission of the Report, by the Expert Committee constituted for suggesting a comprehensive plan for controlling floods and inundation in the coastal deltaic areas of Andhra Pradesh, up to the 30th June 1965

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and copies communicated to all persons concerned.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the State Government of Andhra Pradesh, with a request to them for publishing it in the State Gazette for general information.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Military Secretary to the President, the Lok Sabha/Rajya Sabha Secy., Deptt. of Parliamentary Affairs and the Comptroller and Auditor General of India.

K. G. R. IYER, II. Secy

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-1, the 9th March, 1965

No. 38/7/64-Adv.—In pursuance of Rules 4 and 19 of the Rules for State Awards for Printing and Designing, promulgated in this Ministry's Notification No. 41/23/58-AB dated the 21st March, 1960, as amended by Notification No. 23/19/62-Adv. dated 14th February, 1964, the Central Government have decided that the existing entries at Serial Nos. 8 and 18 in Rule 4 and Rules 6 and 8 shall be substituted by the following, viz. :—

Categories in which prizes will be awarded

4. Prizes shall be awarded in the following categories :—
8. Annuals.
18. Publicity Booklets and Art Magazines.

Eligibility for admission to the competition for award of prizes

6. Without prejudice to the provisions of rules 8 and 9, any production of a Category mentioned, in rule 4, produced wholly in the Union of India during a year, from 1st January to 31st December, for which the award is made, shall be eligible for the competition for the award.

NOTE.—(1) The aforesaid change to the calendar year will be effective from the 11th State Awards for Printing and Designing. Entries for the 10th State Awards for Printing and Designing shall be invited in respect of material produced during the period 15th August, 1963 to 31st December, 1964.

- (2) It is essential that the designing of the various entries, as well as their printing, are completely executed in India; otherwise, they will not be eligible for the award of a prize.

Entries of competition for the award of prize and manner of submission of entries.

8. Entries shall be invited through a Press Note, or by any other means of notifying the public that the Government may deem fit, from printers, publishers, advertisers, advertising agencies, commercial art houses etc. The note or notice shall specify a date not less than 30 days from the date of issue of the Press Note, or other notice for submission of entries.

S. PADMANABHAN, Under Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

RESOLUTION

New Delhi, the 9th March 1965

No. 14(30)/64-EWI.—The Government of India have decided further to extend to the 30th April, 1965 the period in which the Study Team on procedures and practices in the Central Public Works Department set up vide Resolution No. 14(30)/64-EWI, dated the 17th August, 1964, is expected to submit its report.

ORDER

2. ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

R. C. MEHRA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 4th March 1965

No. WB-3(3)/65.—The Central Wage Board for rubber plantations industry, set up by the Government of India by their Resolution No. WB-3(5)/61/2, dated the 7th July 1961, has made recommendations, as shown in the appendix, in regard to the wage structure of the field and factory workers.

2. Government have decided to accept the Wage Board's recommendations and to request the employers to implement the same as early as possible.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

R. L. MEHTA, Additional Secy.

APPENDIX

CENTRAL WAGE BOARD FOR RUBBER PLANTATION INDUSTRY

The Central Wage Board for Rubber Plantation Industry has reached unanimous conclusions about the wage rates of field and factory workers that should prevail in rubber plantation industry for five years with effect from 1st May 1964. The Board has taken decisions in respect of certain other incidental matters too; but the Board is not in a position to finalise its report as wages of clerical, medical, teaching staff, supervisors, etc. employed in rubber plantations have yet to be settled. The Board will therefore require some more time to submit its report to Government. In the meanwhile, the cost of living has increased. The Central Wage Board for Tea Plantation Industry has granted a second interim wage increase with effect from 1st May 1964 for tea workers in the South. This Board has not recommended a second interim increase, as it was finalising the wage structure to have effect for five years. Labour working in Coffee Plantations have also got increased wages as a result of the recommendations of the Central Wage Board for Coffee Plantation Industry. As this Board has also decided to recommend higher wages to the workmen with effect from 1-5-64, it considers that the benefit of its recommendations should be made available immediately to the field and factory workers in rubber plantations. Accordingly, the Board recommends the following daily wage rates for the workers in rubber plantation industry from 1st May 1964 :

(A) Kerala and Madras

- (1) Wages of the time-rated field workers should be as under :—

Men	Rs. 2.10
Women	Re. 1.80
Adolescents	Re. 1.31
Children	Re. 1.05

- (2) Wages of factory workers should be as under :—

Men	Re. 2.30
Women	Re. 1.95
Adolescents	Re. 1.44

- (3) Piece rates and fall back wages for Tappers :

- (a) For the purpose of piece rates, rubber estates should be classified into undermentioned seven classes depending upon the yield per acre for the previous year :

Class	Yield
I	Up to 110 Kg.
II	More than 110 Kg. up to 180 Kg.
III	More than 180 Kg. up to 270 Kg.
IV	More than 270 Kg. up to 360 Kg.
V	More than 360 Kg. up to 450 Kg.
VI	More than 450 Kg. up to 540 Kg.
VII	More than 540 Kg.

- (b) The standard out put that should be co-related to the classification mentioned in (a) should be as follows :

Class	Standard daily output per tapping block
I	1½ Kg.
II	3 Kg.
III	5 Kg.
IV	7 Kg.
V	10 Kg.
VI	12½ Kg.
VII	15 Kg.

- (c) The tapping block for ordinary tapping system should be as under :—

- (i) 250 trees where stand per acre is 100 or below;
- (ii) Up to 300 trees in other cases as at present.

- (d) The tappers should be paid a fall back wage of Re. 1.04 and in addition to it they should be paid wages depending upon their output at the rates mentioned below :

Class	Rate in paise per ½ Kg. up to stan- dard output	Rate in paise per ½ Kg. for output above the stan- dard output
I	39	7
II	20	7
III	13	8
IV	09 ½	8
V	8.3	10
VI	6.64	10
VII	5.5	10

(B) *Mysore*

- (1) The wages of time-rated field workers should be as under :

Men	Re. 1.80
Women	Re. 1.40

Adolescents Re. 1.10

Children Re. 0.90

- (2) The wages of factory workers should be as under

Men Re. 1.90

Women Re. 1.50

Adolescents Re. 1.15

- (3) Piece rates and fall back wages for tappers :

For the purpose of piece rates, classification of rubber estates, standard output co-related to the classification and the rates of wages of piece rated tappers depending upon their output should be the same as mentioned in the case of Madras and Kerala States, except that the fall back wage in Mysore State should be Re. 0.74 per day.

The Board's recommendations regarding wages of labour for subsequent years will be included in the Board's final report.

N. AHMED

Secretary,

Colombatore, dated the 29th January 1965.

(Sd.) Chairman

and Members.